



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-16092020-221770  
CG-DL-E-16092020-221770

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245।  
No. 245।

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
जांच शुरुआत अधिसूचना  
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020  
(मामला संख्या: ए डी (ओआई) 29/2020)

**विषय:** चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडियम हाइड्रोसल्फाइट” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 6/35/2020-डीजीटीआर.—1.** ट्रांसपेक-सिलोक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडियम हाइड्रोसल्फाइट” अथवा “एसएचएस” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

#### **क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सोडियम हाइड्रोसल्फाइट” है, जो जिंक या सोडियम फार्मेट के प्रयोग द्वारा उत्पादित हो तथा “हाइड्रोसल्फाइट कंसन्ट्रेट” अथवा “सोडियम डिथियोनाइट” अथवा “सोडियम हाइड्रोसल्फाइट” या “एसएचएस” के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सफेद या ग्रेइस सफेद पावडर होता है जो तीखी गंध के साथ अन्य दृश्य कणों से मुक्त होता है तथा जिसका क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$  है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विविध औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वस्त्र, साबुन, शीरा, ग्लू और रिज्यूसिंग एजेंट में किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-28 के सीमा शुल्क कोड 28311010 तथा 28321020 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

#### **ख. समान वस्तु**

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### **ग. घरेलू उद्योग**

6. यह आवेदन ट्रांसपेक-सिलोक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी किसी आयातक से संबंधित हैं।

7. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग माना गया है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

#### **घ. पाटन का आधार**

##### **क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

8. चीन जन. गण. के लिए आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(I) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। चीन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ में तर्कसंगत योग करते हुए उसके आधार पर किया गया है।

#### **ख. कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

9. यह अनुरोध किया गया है कि कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को अपनाकर परिकलित किया गया है।

#### **ग. निर्यात कीमत**

10. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांघिकी महानिदेशालय से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

#### **घ. पाटन मार्जिन**

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

#### **इ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्लासकारी प्रभाव के के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, मालसूची और लाभ, नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के संबंध में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है जो पाटनरोधी जांच शुरुआत को उचित ठहराती है।

#### **ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

13. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

#### **झ. संबद्ध देश**

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य हैं।

#### **ज. जांच की अवधि (पीओआई)**

15. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में 2016- 2017, 2017- 2018, 2018- 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

**क्ष. प्रक्रिया**

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**अ. सूचना प्रस्तुत करना**

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) तथा [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

18. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**ट. समय-सीमा**

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 37 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) तथा [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध

में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **इ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

31. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

#### **इ. असहयोग**

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2020

(Case No. AD (OI) – 29/2020)

**Subject:** Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Sodium Hydrosulphite” originating in or exported from China PR and Korea RP.

**F. No. 6/35/2020-DGTR.—1.** Transpek-Silox Industry Private Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification,

Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of “Sodium Hydrosulphite” or “SHS” (hereinafter also referred as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as “subject countries”).

2 The Applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. Product under consideration**

3 The product under consideration in the present investigation is “Sodium Hydrosulphite”, whether produced using Zinc or Sodium Formate, also known as “Hydrosulphite Concentrate” or “Sodium Dithionite” or “Sodium Hydrosulfite” or “SHS”. It is a white or grayish white powder, free from visible foreign particles with pungent odour and its crystalline chemical formula is  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ . The product under consideration is used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent.

4 The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under the custom code 28311010 and 28321020. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

**B. Like article**

5 The Applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country

**C. Domestic industry**

6 The application has been filed by Transpek-Silox Industry Private Limited. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or importer in India.

7 As per evidence available on record, the Applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**D. Basis of alleged dumping**

**a. Normal value for China PR**

8 For China PR, the Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of

provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules. The normal value for China has been constructed on the basis of cost of production in India, with a reasonable addition for selling, general and administrative expenses and profits.

**b. Normal value for Korea RP**

9. It is submitted that other documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in Korea RP are not available in the public domain. The Normal value for Korea RP has therefore been constructed by adopting cost of production in India.

**c. Export price**

10. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

**d. Dumping margin**

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows dumping margin above the de-minimis level in respect of the product under consideration from the subject countries. There is *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**E. Injury and Causal Link**

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished *prima facie* evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that their performance has been adversely impacted in respect of sales, capacity utilization, market share, inventories and decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of product under consideration at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of anti-dumping investigation.

**F. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**G. Subject Countries**

14. The subject countries for the present investigation are China PR and Korea RP.

**H. Period of Investigation (POI)**

15. The period of investigation (POI) in the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

**I. Procedure**

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**J. Submission of Information**

17. In view of the special circumstances arising out of COVID- 19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

18. The known producers/exporters in the subject countries, Governments of the subject countries through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**K. Time Limit**

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) within 37 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**L. Submission of information on confidential basis**

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **M. Inspection of Public File**

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

### N. Non-cooperation

32 In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority